

अंतरिम

GUG

का सारांश 2024-25



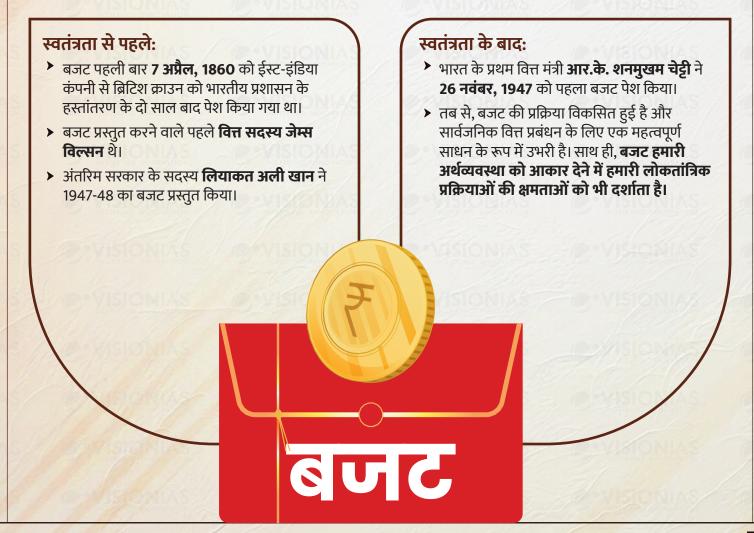
बजट क्या है?

- संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) के रूप में जाना जाता है।
 - गौरतलब है कि संविधान में "बजट" शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।
 - यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है।
- संघीय बजट को राजस्व बजट (सरकार की कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय) और पूंजीगत बजट (सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान) में वर्गीकृत किया जाता है।
 - बजट को तैयार करना:
 - वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है।
 - एक वर्ष का बजट आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
 - यह मोटे तौर पर विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों और इस काम में लगे विभाग के प्राधिकारियों की ओर से दिए गए व्यय या भुगतान और प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है।
 - बजट को नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है (अर्थात् किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में जो कुछ भी प्राप्त होने या भुगतान होने की उम्मीद है)।
- बजट की प्रस्तुति:
 - राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराता है।
 - संसद में, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। इसे दो भागों- भाग A और भाग B में प्रस्तुत किया जाता है:
 - बजट का भाग A: यह बजट का समष्टि-आर्थिक (Macro-Economic) भाग होता है। इसके तहत सरकार की अलग-अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए निधि भी आवंटित की जाती है।



- 🄈 **बजट का भाग B:** यह **वित्त विधेयक** से संबंधित होता है। इसमें आयकर संबंधी संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं।
- 🔈 **बजट में पेश किए जाने वाले मुख्य दस्तावेज़:** वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा, संसद में पेश किए जाने वाले प्रमुख बजट दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
 - वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112 के तहत),
 - अनुदान-मांगें (अनुच्छेद 113 के तहत),
 - > वित्त विधेयक (अनुच्छेद 110 के तहत), और
 - FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति का विवरण-
 - समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण (Macro-Economic Framework Statement)।
 - मध्याविध राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य-योजना संबंधी विवरण (Medium-Term Fiscal Policy) cum Fiscal Policy Strategy Statement)
- बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
 - > व्यय बजट
 - > प्राप्ति बजट
 - > व्यय की रूपरेखा
 - बजट एक नज़र में
 - बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं
 - बजट 2023-24 की घोषणाओं का कार्यान्वयन

बजट का इतिहास



बजट की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है:



अंतरिम बजट 2024-25

- 🕨 चूंकि 2024 चुनावी साल है, इसलिए सरकार ने अभी पूर्ण बजट की बजाय **अंतरिम बजट** पेश किया है।
- ▶ **अंतरिम बजट:** यह एक **अल्पकालिक वित्तीय योजना** होती है। इसे अगले चुनाव तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है।
 - पूर्ण बजट के विपरीत, अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अविध में सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय <mark>के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है। **पूर्ण बजट** में सरकार के राजस्व, व्यय, आवंटन एवं आर्थिक नीतियों के विवरण सहित **सरकारी**</mark> वित्त के हर पहलू को शामिल किया जाता है।
 - अंतरिम बजट के लिए सरकार, संसद में लेखानुदान पारित कराती है।
- ▶ **लेखानुदान (Vote-on-account): संविधान के अनुच्छेद 116** के अनुसार, लेखानुदान तत्काल व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **भारत की संचित निधि से सरकार को अग्रिम भुगतान** का प्रावधान करता है।



अंतरिम बजट 2024-25

बजट का विजन: 2047 तक विकसित भारत- यह परिकल्पना सरकार की उस "समृद्ध भारत की है जो आधुनिक अवसंरचना के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी नागरिकों और सभी क्षेत्रों को अपना सामर्थ्य हासिल करने के अवसर दे रहा है।"

बजट का विकास मंत्र: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का समग्र 'राष्ट्रीय दृष्टिकोण'।

- समावेशन के सभी तत्वों को शामिल करना इस बजट का दर्शन है।
 - सामाजिक समावेशिता: समाज के सभी वर्गों के कवरेज के जिरए।
 - भौगोलिक समावेशिता: देश के सभी क्षेत्रों के विकास के जिरए।



फोकस के क्षेत्र



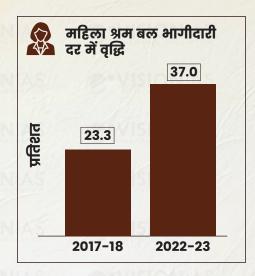
फोकस के क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां:

▶ गरीब (Poor)

- > गरीबी उन्मूलन: 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली।
- > प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): पी.एम.-जन धन खातों के उपयोग से 34 लाख करोड़ रुपये के DBT के जरिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है।
- > पी.एम.-स्वनिधि
 - 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान की गई है।
 - 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी बार क्रेडिट मिला है।
- > पी.एम.-जनमन योजना: इसकी सहायता से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों तक पहुंचने में मदद मिली है।
- > पी.एम.-विश्वकर्मा योजना: 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जा रही है।

महिलाएं

- महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 30 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है।
- पिछले दस वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई
- > STEM कोर्स में, लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43 प्रतिशत है यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है।
- > 'तीन तलाक' को गैर-कानूनी बनाकर महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा की गई है।
- लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों को **आरक्षित** करने के लिए **128वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी** दे दी गई है।
- > ग्रामीण क्षेत्रों में **पी.एम. आवास योजना** के तहत **70 प्रतिशत से अधिक मकान** महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिकों के रूप में प्रदान किया गया है।



यवा (यथ या अमृत पीढी)

- > राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरूआत कर रही है।
- > पी.एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI): पी.एम स्कूल (पी.एम. श्री) में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है, और बच्चों का समग्र एवं चहुंमुखी विकास किया जा रहा है।
- > **कौशल भारत मिशन:** 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख युवाओं के कौशल को अपग्रेड किया गया है, और 3,000 नए ITIs की स्थापना की गई है।
- > उच्चतर शिक्षा हेतु नए संस्थान: 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIMs, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- > पी.एम. मुद्रा योजना: कुल मिलाकर 22.5 लाख करोड के 43 करोड लोन स्वीकृत किए गए हैं।
- फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टार्ट-अप क्रेडिट गारंटी योजनाएं: युवाओं की सहायता करने एवं उन्हें 'रोजगारदाता' बनाने के लिए।
- > खेलों में युवा:
 - 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों की पदक तालिका में अब तक का सबसे बेहतरीन स्थान हासिल हुआ है।
 - 2023 में शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रग्गनानंद ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के विरुद्ध कड़ी चुनौती पेश की।
 - भारत में वर्तमान में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जबिक 2010 में इनकी संख्या 20 से कुछ ही ज्यादा थी।

अन्नदाता (किसान)

- पी.एम.-किसान सम्मान योजना: लघु एवं सीमांत किसानों सिहत ११.८ करोड किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही
- > पी.एम. फसल बीमा योजना: 4 करोड किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
- > **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार:** 1,361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार हो रहा है तथा 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं।
- अन्य उपाय, जैसे- किसान-केंद्रित नीतियां, आय सहायता, मूल्य और बीमा समर्थन के माध्यम से जोखिमों का कवरेज, स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।



अमृत काल के लिए रणनीति

सतत विकास

- 2070 तक 'नेट ज़ीरो' हासिल करने की प्रतिबद्धता
 - पवन ऊर्जा के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग
 - कोयला गैसीकरण एवं द्वीकरण क्षमता की स्थापना
 - सी.एन.जी., पी.एन.जी. और संपीडित बायोगैस का चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सम्मिश्रण
 - बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता
- छत पर सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित करना
 - > 1 करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
- सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अपनाना
- विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन करके ई-वाहन परिवेश को मजबूत करना
- पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिए बायोमैन्युफैक्चिरंग और बायो-फाउँडी संबंधी नई योजना शुरू की जाएगी।

अब तक की उपलब्धियां

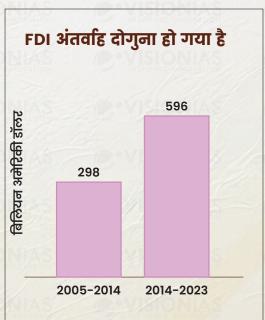
- ▶ PMUY के तहत 10 करोड एल.पी.जी. कनेक्शन
- ▶ 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख LED ट्यूब लाइट
- UJALA के तहत 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए गए
- SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं
- गैर-जीवाश्म ईंधन की स्थापित ऊर्जा क्षमता 2004 के 30.4% से बढ़कर 2023 में 43.9% हो गई

बुनियादी ढांचा और निवेश

- पी.एम. गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना ताकि लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हो सके और लागत कम हो सके।
 - > द्विपक्षीय निवेश संधियों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर वार्ता की जाएगी।
 - उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास।
 - मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना।

अब तक की उपलब्धियां





समावेशी विकास

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम: राज्यों को तेजी से विकास और रोजगार सृजन में सहायता करेगा।
- पूर्वोत्तर का विकास: पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाना।
- पी.एम. आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना: मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने/ बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जाएगी।
- मौजूदा अस्पतालों के इन्फ्रास्ट्क्चर का उपयोग करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लडिकयों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल: कार्यान्वयन में तालमेल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।
- बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर, बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने में तेजी लाई जाएगी।
- टीकाकरण के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया नया यू-विन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार हेत् सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।

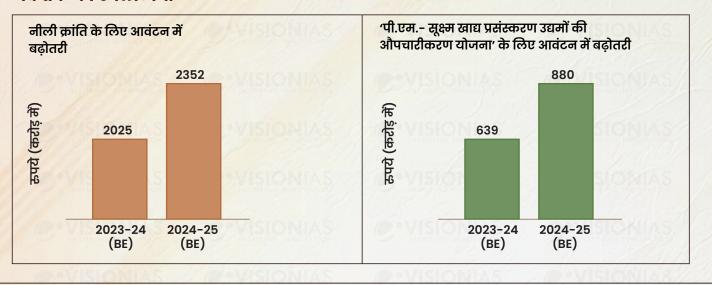
अब तक की उपलब्धियां

РМАУ के लिए आवंटन आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास (११२) बढ़ाया गया पहली तिमाही के भीतर प्रसव-पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का % प्रति लाख जुनसंख्या पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत नामांकन की संख्या 80671 13195 89 **इपये (करोड़ में)** प्रतिशत संख्या 68 79590 1737 2023-24 2024-25 Oct-23 2018 Oct-23 2018 (BE)

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

- **फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, जैसे-** उपज एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण एवं विपणन और ब्रांडिंग।
- सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो DAP के उपयोग का विस्तार किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर तिलहन अभियान: तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी।
- 🕨 खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने तथा दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने हेतू **डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम** तैयार किया जाएगा।
- > प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जलीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके, निर्यात को दोगुना किया जा सके एवं रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सके।
 - इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 5 एकीकृत एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे।
- 🄈 ब्लू इकोनॉमी 2.0 को बढ़ावा देना: जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बह्-क्षेत्रक दृष्टिकोण के साथ, तटीय एक्वाकल्चर और मारिकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी।

अब तक की उपलब्धियां



पर्यटन

- > राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का समग्र रूप से विकास करने, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- स्विधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की जाएगी।
- पर्यटन विकास के वित्त-पोषण के लिए राज्यों को समान आधार पर ब्याज मृक्त दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा।
- लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों के लिए बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

अन्य उपाय

- लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड से बढाकर 3 करोड़ करना।
 - लखपित दीदी का तात्पर्य स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) की ऐसी मिहला सदस्यों से है जो प्रित पिरवार प्रित वर्ष कम-से-कम १ लाख रुपये की स्थायी आय अर्जित करती हैं।
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना
 - पचास साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।
 - > रक्षा उद्देश्यों और 'आत्मनिर्भरता' में तेजी लाने के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने हेतु एक नई योजना शुरू की जाएगी।
- 🎤 **'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार:** 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में संवृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए पचास वर्ष के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।
- <mark>सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना: तीव्र</mark> जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न चुनौतियों <mark>का</mark> समाधान करने एवं 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कियाँ जाएगा।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर

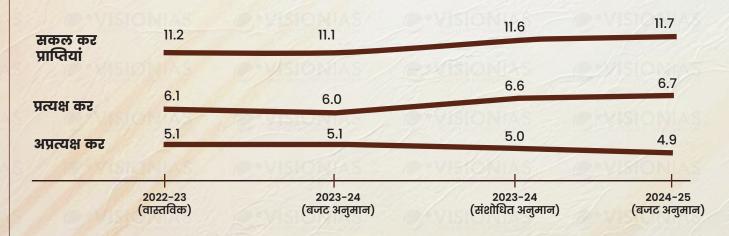
- पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह तीन गुना से अधिक हो
- टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना की वृद्धि हुई है।
- टैक्स रिटर्न को प्रॉसेस करने का औसत समय 2013-14 में 93 दिन था, जो **घटकर** 2023-24 में 10 दिन हो गया है।
 - 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं पर कोई कर देनदारी नहीं है।
 - 🕨 खुदरा व्यवसायों के लिए प्रिजम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है।
 - 🕨 मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दी गई है।
- करदाता सेवाओं में सुधार:
 - फेसलेस असेसमेंट और अपील
 - टैक्स रिटर्न पहले से भरना और नया फॉर्म **26AS**

अप्रत्यक्ष कर

- > वित्त वर्ष 2024 में औसत मासिक सकल GST संग्रह दोगुना होकर 21.66 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- > GST के लागू होने बाद की अवधि (2017-2023) में राज्यों में कर उछाल (Tax buoyancy) देखा गया है। यह 2012-2016 की अवधि में 0.72 था, जो बढकर 2017-2023 में 1.22 हो गया है।
- > अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लॉजिस्टिक लागत एवं उनकी कीमतों में कमी आई है।
- 2019 से इम्पोर्ट रिलीज टाइम में कमी आई है:
 - अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पर 47 प्रतिशत कम हुआ है;
 - एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर 28 प्रतिशत कम हुआ है;
 - समुद्री बंदरगाहों पर 27 प्रतिशत कम हुआ है।
- > टैक्स आर्बिट्राज और चुंगी (Octroi) को समाप्त करके आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाया गया है।

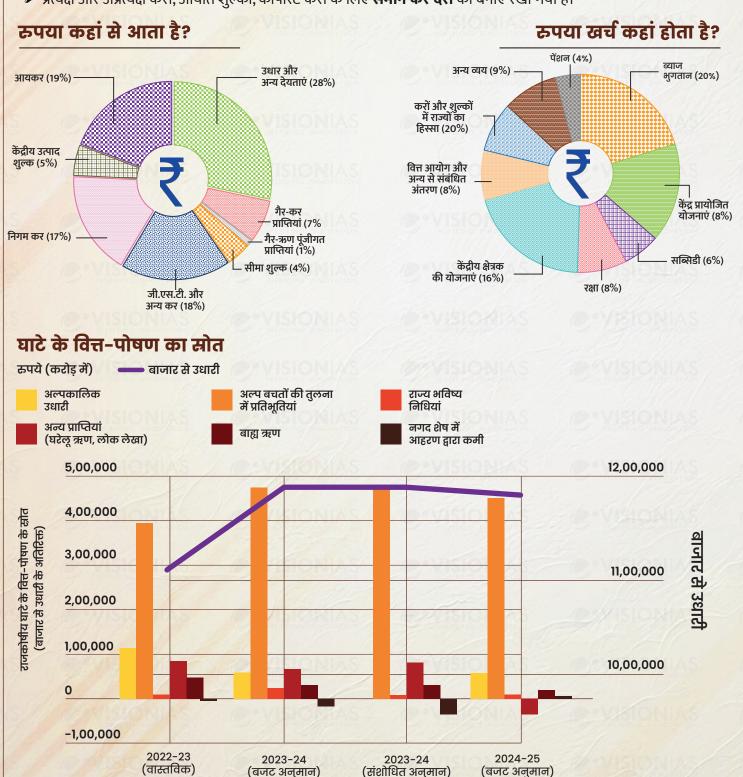


कर प्राप्तियों का समग्र रुझान:

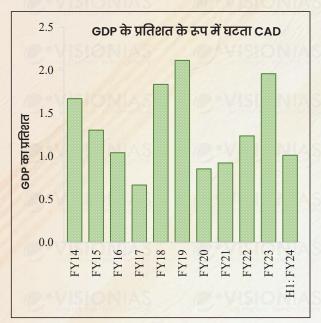


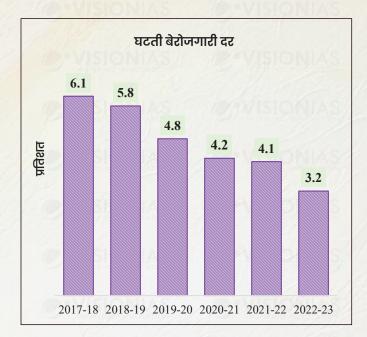
कर प्रस्ताव

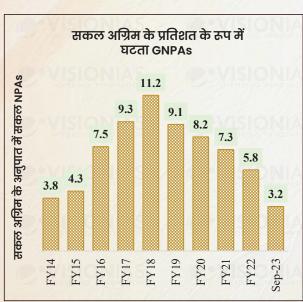
- ▶ **कराधान में निरंतरता:** स्टार्ट-अप और सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ IFSC यूनिट्स के लिए कर छूट को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- बकाया प्रत्यक्ष कर को माफ़ किया गया है:
 - वित्त वर्ष 2009-10 तक की अविध के लिए 25,000 रुपये तक
 - वित्त वर्ष 2011-15 तक की अविध के लिए 10,000 रुपये तक
 - इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, आयात शुल्कों, कॉर्पोरेट करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखा गया है।

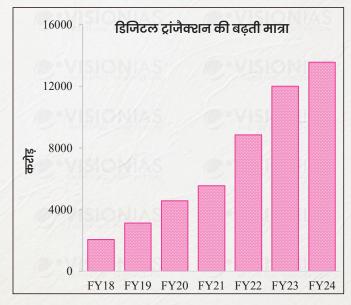


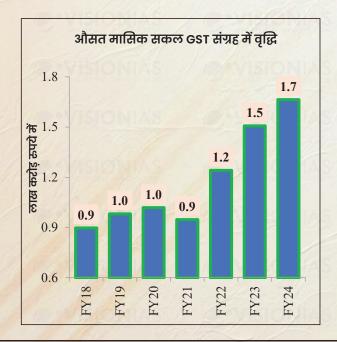
भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन

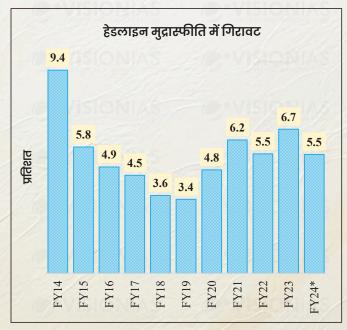












शब्दावलियां

विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)	यह सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है।
चुंगी (Octroi)	यह किसी स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कुछ श्रेणियों की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है।
सॉवरेन वेल्थ फंड्स	ये सरकार के स्वामित्व वाले निवेश साधन होते हैं जो देश के वित्तीय भंडार का प्रबंधन करते हैं। वे दीर्घकालिक धन उत्पन्न करने और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक, बॉण्ड, रियल एस्टेट और अन्य उपकरणों जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।
सीमा शुल्क (Custom Duty)	<mark>यह वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है।</mark>
टैक्स आर्बिट्राज	जब कर दे <mark>यताओं को कम करने</mark> या वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए अलग-अलग कर विनियमों या दरों में अंतर का रणनीतिक रूप से फायदा उठाया जाता है तो उसे टैक्स आर्बिट्राज कहते हैं।
प्रत्यक्ष कर (Direct taxes)	जब कोई व्यक्ति सीधे सरकार को कर का भुगतान करता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसमें आयकर कर, पोल टैक्स, भूमि कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर आदि शामिल हैं।
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)	वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऐसे कर अंतिम उपभोक्ता से विनिर्माता या खुदरा विक्रेता जैसे मध्यस्थ एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए- वस्तु एवं सेवा कर (GST), उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि।
राजस्व प्राप्तियां (Revenue receipts)	यह सरकार को बिना ऋण लिए या मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचे बिना प्राप्त धन है। इसमें कर, <mark>सार्वजनिक उद्यमों से ला</mark> भांश, सेवाओं के लिए शुल्क आदि शामिल होते हैं।
निगम कर (Corporate tax)	यह किसी कंपनी के मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। यह कंपनी की निवल आय पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में वसूला जाता है। इससे सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना के लिए सरकार को राजस्व जुटाने में मदद मिलती है।
कर उछाल (Tax buoyancy)	कर उछाल GDP में वृद्धि के सापेक्ष कर संग्रह में वृद्धि के माप को इंगित करता है। कर राजस्व को तब उछालपूर्ण माना जाता है, जब कर की दरें अपरिवर्तित रहने पर भी GDP में संवृद्धि की तुलना में कर संग्रह में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है।
व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (Viability gap funding)	इसके तहत आर्थिक रूप से न्यायसंगत लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है।
प्रिजम्प्टिव कराधान (Presumptive taxation)	इसके तहत पात्र व्यवसाय अपने टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत को आय के रूप में घोषित कर सकते हैं। यह विस्तृत लेखांकन रिकॉर्ड की आवश्यकता को कम करते हुए कर नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है
मुद्रास्फीति (Inflation)	यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है। साधारणतः मुद्रास्फीति एक माप है जो यह बताती है कि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का एक सेट कितना महंगा हो गया है।
पूंजीगत व्यय (Capital expenditure)	यह विकास हेतु सरकार द्वारा किया गया निवेश है। इसके उदाहरणों में शामिल हैं- मशीनरी, भवन, शिक्षा आदि में निवेश; परिसंपत्तियों का अधिग्रहण; भविष्य में राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में निवेश; आदि।
बजट अनुमान (Budget estimates)	यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय अनुमान होता है। इसके तहत वार्षिक बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूंजी के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। ये अनुमान सरकार के व्यय की मंशा का संकेत देते हैं लेकिन ये सटीक आंकड़े या बाध्यकारी प्रतिबद्धता के सूचक नहीं होते हैं।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)	DBT का उद्देश्य समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभ और सब्सिडी को समय पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करना है। यह बिचौलियों को समाप्त करता है, किसी भी धोखाधड़ी को रोकता है और दक्षता, प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation rate)	यह किसी देश की आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत को दर्शाती है। इसकी गणना श्रम बाजार में सक्रिय रूप से काम कर रहे और काम की तलाश कर रहे लोगों के आधार पर की जाती है

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद १०९	धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद ११०	धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद ११२	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद ११३	प्राक्कलनों के संबंध में संसद में प्रक्रिया
अनुच्छेद ११४	विनियोग विधेयक
अनुच्छेद ११५	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद ११६	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद ११७	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान
अनुच्छेद १५०	संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
अनुच्छेद १५१	ऑडिट रिपोर्ट अस्ति
अनुच्छेद २६५	विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा
अनुच्छेद २६६	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे
अनुच्छेद २६७	आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद २७५	कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
अनुच्छेद २८०	वित्त आयोग
अनुच्छेद 281	वित्त आयोग की सिफ़ारिशें
अनुच्छेद २९२	भारत सरकार द्वारा उधार लेना

39 in Top 50 Selection in CSE 2022







GARIMA LOHIA



UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में





BHARAT JAI PRAKASH MEENA









MEENA

8 in Top 10 Selection in CSE 2021



ANKITA AGARWAL



GAMINI SINGLA



AISHWARYA VERMA



UTKARSH



YAKSH CHAUDHARY



SAMYAK S JAIN



PREETAM KUMAR



HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate-6, Karol Bagh Metro Station, Delhi

MUKHERJEE NAGAR CENTRE

Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, Delhi

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066



SHUBHAM KUMAR CIVIL SERVICES **EXAMINATION 2020**



ENQUIRY@VISIONIAS.IN



/VISION_IAS



WWW.VISIONIAS.IN



/C/VISIONIASDELHI





/VISIONIAS_UPSC



























